मजदूरों से क्रूर मजाक करती सरकार

फरीदाबाद (म.मो.) 21000 मासिक से कम वेतन वाले औद्योगिक मजदूरों के वेतन का साढे चार प्रतिशत ईएसआई के नाम पर वसूली करने के बावजूद सरकार लगातार उन्हें तमाम चिकित्सा सुविधाओं से वंचित करने पर तुली है। विदित है कि ईएसआई निगम पूर्णतया मजदूर के वेतन से काटे गये अंशदान से फल-फूल रहा है। लेकिन इसके बदले जो चिकित्सा सेवा मजदूर को मिलनी चाहिए उसका नितांत अभाव है।

मजदूरों को यह चिकित्सा सेवा दो तरह से प्रदान की जाती है। एक तो सीधे तौर पर ईएसआई कार्पोरेशन अपने अस्पताल व डिसपेंसरी चला कर जैसे कि यहां एन.एच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गुड़गांव के दो छोटे-छोटे अस्पताल आदि। दूसरे, राज्य सरकार के माध्यम से। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा ईएसआई हैल्थकेयर निदेशालय खोला हुआ है। इसका मुख्य आफिस पंचकूला में है जो राज्य के श्रम मंत्रालय के आधीन रहता है। ईएसआई कार्पोरेशन की नियामवली के अनुसार इस निदेशालय को राज्य भर में आवश्यकता अनुसार डिस्पेंसरियां व अस्पताल चलाने का पूरा

अधिकार दिया गया है। इसके लिए निदेशालय सभी प्रकार की भर्तियां, नियुक्तियां, तबादले आदि करने के साथ-साथ तमाम तरह के उपकरण व दवायें आदि की खरीददारी कर सकता हैं डिस्पेंसरियों व अस्पताल के इमारतों के निर्माण का तमाम खर्च भी कार्पोरेशन ही वहन करती है। इस सारे काम के लिए निदेशालय हर साल बाकायदा बजट तैयार करता है। जिसका केवल आठवां भाग राज्य सरकार और शेष कार्पोरेशन वहन करती है यानी बजट यदि 8 रुपए का है तो राज्य सरकार मात्र एक रुपया और शेष 7 रुपए कार्पोरेशन वहन करती है। राज्य में, 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 28 लाख मजदूर इसमें कवर्ड है। इनको चिकित्सा सुविधायें देने के लिए राज्य भर की डिस्पेंसरियों में, ईएसआई मैनुअल के मुताबिक 1400 डाक्टर व 7000 अन्य स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए, अस्पतालों का स्टाफ इसके अलावा होगा। लेकिन जरूरत के विपरीत राज्य भर की डिस्पेंसरियों में तैनाती मात्र 225 डाक्टरों व 600 स्टाफ की है। पहले से ही स्टाफ के टोटे की अवस्था में देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत ने डिस्पेंसरियों के स्टाफ के बल पर हिसार का देवीलाल कोविड अस्पताल चलाने का एलान कर दिया है। बिना यह सोचे समझे कि जिनके पैसों से यह सब चल रहा है, वे कौन से कुएं में पड़ेंगे?

दुर्भाग्य की बात यह है कि 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए खट्टर सरकार ने कुछ पोस्टें छोटे स्टाफ के लिए निकाली थी लेकिन उसके बाद आज तक कोई भर्तियां नहीं की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईएसआई हैल्थ केयर को ठीक से चलाने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। बजट बनाने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। यदि सरकार की जनता से दुश्मनी न हो तो वह कम से कम 1200 करोड़ का बजट बनाके मात्र 150 करोड़ अपने यहां से खर्च करके शेष 1050 करोड़ ईएसआई कार्पोरेशन से ले सकती है जबकि सरकार बजट बनाती है 150 करोड़, इस बार बनाया है कि 239 करोड का, इसमें से भी पता नहीं कितना खर्च व कितना लैप्स होगा। बीते सभी वर्षों में लगभग 10-20 करोड़ का बजट लैप्स होता रहा है। बजट लैप्स कराना मंजूर है लेकिन दवायें व आवश्यक उपकरण नहीं खरीदे जाते और तो और बीते करीब ढाई साल रेबीज (कुत्ता काटे) के इन्जेक्शन तक नहीं खरीदे गये हैं जबकि साल भर में बीसियों हजार केस कुत्ता काटे के आते हैं।

एक और गौरतलब बात यह भी है कि राज्य सरकार इस धंधे को छोड़ना भी नहीं चाहती। जब भी कार्पोरेशन राज्य सरकार से कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी टेक ओवर करने का प्रस्ताव देती है तो राज्य सरकार पूरा ड्रामा करती है। राज्य सरकार को ऐसा लगता हे जैसे उनके साम्राज्य में सेंधमारी हो रही है। बीते दिनों जब एन.एच-3 का अस्पताल टेकओवर करके मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव कार्पोरेशन ने भेजा जो तत्कालीन हुड्डा सरकार व उसके श्रममंत्री स्वर्गीय शिवचरण लाल शर्मा ने पूरी नाटकबाजी के बाद स्वीकार किया था। यानी राज्य सरकार न तो खुद ढंग से काम करना चाहती है न कार्पोरेशन को करने देना चाहती है। इन दोनों के बीच, अपने वेतन से ईएसआई को पैसा देकर भी, भुगत रहा है बेचारा गरीब मजदूर।

खट्टर को खदेड़ा हिसार वालों ने...

पेज एक का शेष

अंधभक्त गोपाल शर्मा का बयान पूरी तरह से भ्रामक व झूठ की बुनियाद पर खड़ा करने का प्रयास है। हकीकत यह है कि खट्टर वहां कोई अस्पताल खोलने नहीं बल्कि यह दिखाने के लिये आये थे कि वे किसान आंदोलनकारियों के विरोध के बावजूद भी हिसार में घुसने का सामर्थ्य रखते हैं। वैसे भी यह आना कोई आना नहीं था अत्यधिक भारी पुलिस बल के बावजूद वे आये भी तो चोरों की तरह लुकते-छिपते।

रही बात अस्पताल की तो वह पाखंड के सिवाय कुछ भी नहीं है। दरअसल जिस तथाकथित देवीलाल अस्पताल का उद्घाटन खट्टर कर गये हैं अपने नाम का पत्थर लगवा गये हैं वह उद्योगपति जिंदल कम्पनी का स्कूल जो फिलहाल लॉकडाउन के चलते बंद है। स्कूल जिंदल कारखाने के निकट है। इसलिए फिलहाल कारखाने से आक्सीजन की पाइप लाइन भी ले ली गयी है। स्कूल के कमरों में खाट बिछा देने से वह अस्पताल नहीं बन जाता। अस्पताल के लिये डाक्टर व अन्य आवश्यक स्टाफ लेबोरेट्री, रेडियोलॉजी आदि के अनेकों उपकरणों की जरूरत होती है, जो यहां कुछ भी नहीं है। आईसीयू और वेंटिलेटर का तो नामोनिशान नहीं है। कुल मिलाकर यह तथाकथित अस्पताल ऐसा ही है जैसे कोई मरीज अपने घर में लेटा हो।

पहले से ही चने के झाड़ पर चढ़े देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला को बाजरे के झाड़ पर चढ़ाते हुए खट्टर ने इस नकली अस्पताल को देवीलाल का नाम दे दिया। झाड़ पर चढ़े चौटाला के सामने जब यह सवाल है कि अस्पताल के लिए स्टाफ तो है ही नहीं तो उन्होंने अपने चेले एवं श्रम मंत्री अनूप धानक को आदेश दिया कि वह अपने मातहत चलने वाले ईएसआई हेल्थ केयर से स्टाफ मंगाकर यहां तैनात कराये। धानक के आदेश पर डायरेक्टर डा अनिल मलिक ने फरीदाबाद सहित अन्य कई क्षेत्रों की ईएसआई डिस्पेंसरियों से तमाम स्टाफ निकाल कर हिसार व ऐसे ही एक नकली अस्पताल पानीपत में भेजने के आदेश जारी कर दिया। खबर लिखे जाने तक आदेश किसी भी संबंधित स्टाफ तक नहीं पहुंचे थे। जानकार बताते है कि आदेश पहुंचने के बाद भी किसी के भी यहां से जाने की संभावना न के बराबर है और किसी अनिच्छुक स्टाफ को अस्पताल में लगाया तो जा सकता है परन्तु उससे काम नहीं लिया जा सकता।

खट्टर ने सरकार का करीब 28.5 करोड़ रुपया खर्च करके इस नकली अस्पताल का पाखंड केवल इसलिये किया था कि इसके बहाने वह इस हिसार शहर में घुस पायेंगे जहां के किसानों से उन्हें तड़ीपार करते हुए उनके प्रवेश पर रोक लगा रखी है। किसी भी सीएम के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नही सकती कि वह अपने राज्य के किसी एक जिले में, सारी ताकत लगाने के बावजूद घूम न सके। वैसे हालात ये है कि आज खट्टर एवं उनके मंत्री सिवाय गुड़गांव और फरीदाबाद शहर के अलावा किसी भी शहर में घूम पाने की स्थिति में नहीं है, देहातों की बात ही छोड़ दीजिये। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि जनता के टैक्स से वसूले गये 28.5 करोड़ की बर्बादी का क्या जवाब है खट्टर के पास? स्कूल 2 नहीं, 4 महीने बाद खुल ही जायेगा, बेशक न भी खुले 10-20 दिन बाद इस नकली अस्पताल में एक भी मरीज दिखाई देने वाला नहीं। खबर लिखे जाने तक इस नकली अस्पताल में मात्र 131 पेशेन्ट ओपीडी में आये,101 दाखिल किये गये, 60 मौजूद है, 9 डिसचार्ज हो गये, 12 मर गये, 8 भाग गये 12 रैफर हुए।

यहां एक और बड़ा सवाल लॉकडाउन कानून का भी खड़ा कर गये खट्टर जी। वैसे तो ब्याह-शादी मरने-जीने पर 11 लोगों से अधिक के एकत्रित होने पर पाबंदी है, उल्लंघन करने वालों पर पुलिस बेजा सख्ती करती है, परन्तु क्या खट्टर व उनके लग्गुए-भग्गुए कानून से ऊपर है जो इस तथाकथित उद्घाटन में आकर सैकड़ों लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे? वैसे खट्टर ही क्या तमाम संघी अपने आपको हर कानून से ऊपर समझते हैं।

खट्टर के इस व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप हिसार के लोगों ने को टीकाकरण सहित तमाम लॉकडाऊन नियमों को तोड़ते हुए सीविल नाफर्मानी आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा लाठीचार्ज के विरोध में अनेकों ग्राम पंचायतों ने खट्टर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को गांव में न घुसने देने का फैसला किया है। यदि कोई घुसेगा तो उसे पीटा जायेगा।

ईएसआई डिस्पेंसरियों को बंद करने का तीखा विरोध

फरीदाबाद, (ममो) ट्रेड यूनियन काउंसिल (फरीदाबाद) ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईएसआई डिस्पेंसरियों को बंद करने की योजना का विरोध किया है । काउंसिल के प्रतिनिधियों ने सिविल सर्जन, ईएसआई हेल्थ केयर, फरीदाबाद के ज़रिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन दिया है । जिसमें मांग की गई है कि डिस्पेंसरियों के डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के स्थानांतरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए । कोविड महामारी से हो रही जान माल की तबाही को रोकने में नाकाम हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने आनन-फानन में बिना तैयारी के पानीपत और हिसार में विशेष कोविड अस्पताल बनाया है ।

हरियाणा सरकार के मातहत काम करनेवाला स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की नई भर्ती करने के बजाय मजदूरों के पैसे से चलने वाली ईएसआई के डॉक्टर और अन्य स्टाफ को स्थानांतरित कर हिसार और पानीपत में लगा रहा है ।

फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज को पहले ही कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है । वहां पर नॉन कोविड मरीजों की ओपीडी बंद कर दी गई है , जिससे हजारों मजदूर दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सेक्टर 8 स्थित ईएसआई अस्पताल डॉक्टर और अन्य स्टाफ की कमी से कुप्रबंधन का शिकार है । फरीदाबाद में ईएसआईसी की 12 डिस्पेंसरी हैं । मजदूर इन्हीं डिस्पेंसरी में अपने इलाज के लिए निर्भर थे ।

अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पूरे हरियाणा राज्य की ईएसआई डिस्पेंसरियों के डॉक्टरों और स्टाफ को हिसार व पानीपत में स्थानांतरित कर मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रहा है । ईएसआईसी मेडिकल कालेज, अस्पताल व डिस्पेंसरियों में पहले से ही डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की भारी कमी है ।

केवल फरीदाबाद में 5.30 लाख आईपी

हैं । इनके परिवारों के सदस्यों को जोड़ दिया जाए तो संख्या कम से कम 14-15 लाख बनती है । इस बारे में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया है । फरीदाबाद की ट्रेड यूनियन काउंसिल कोविड अस्पताल का विरोधी नहीं है । कोविड मरीजों को विशेष ट्रीटमेंट दे कर उनके जीवन की रक्षा करना जरूरी है । लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने ईएसआई आईपी होल्डर मजदूरों और उनके मरीजों को लात मार कर यह कदम उठाया है । जोकि आईपी मजदूरों के साथ नाइंसाफी है । स्वास्थ्य विभाग के मजदूर विरोधी इन कदमों का काउंसिल विरोध करता है । सिविल सर्जन, हेल्थ केयर फरीदाबाद को ज्ञापन देते समय सीटू, एटक, एचएमएस,एसकेएस, इंकलाबी मजदूर केंद्र, औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि कामरेड निरन्तर परासर, कामरेड राजपाल, कामरेड संजय मौर्य, कामरेड नितेश आदि मौजूद थे ।

SOS

आज मजदूर मोर्चा अपने कठिनतम दौर से गुजर रहा है। यदि समय रहते सुधी पाठकों का सहयोग न मिल पाया तो इस निर्भीक एवं जुझारू आवाज का जीवित रहना दूभर हो जायेगा। इसलिये पाठकों से विनम्र निवेदन है कि यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad